भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.07.2019 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1829 का उत्तर

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1829. श्री बी॰वाई॰ राघवेन्द्रः
श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कनार्टक राज्य में नई रेल लाइनों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में परियोजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) राज्य में नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त परियोजना हेतु आबंटित और खर्च की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या उक्त परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

कर्नाटक में रेल परियोजनाओं के संबंध में 03.07.2019 को लोक सभा में श्री बी.वाई. राघवेन्द्र और श्री नलीन कुमार कटील के अतारांकित प्रश्न संख्या 1829 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क), (ख) और (घ): कर्नाटक राज्य में 41746 करोड़ रु. की लागत वाली 4417 किमी लंबाई की कुल 35 परियोजनाएं योजना / अनुमोदन / निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और मार्च, 2019 तक 8402 करोड़ रु. की लागत से 679 किमी लंबाई वाले मार्ग को चालू कर दिया गया है। इनमें से, 26393 करोड़ रु. की लागत वाली 2502 किमी लंबाई की 20 नई लाइन परियोजनाएं और 15353 करोड़ रु. की लागत वाली 1916 किमी लंबाई की 15 दोहरीकरण परियोजनाएं दोहरी / तीसरी / चौथी लाइन के निर्माण की हैं।

पिछले 03 वित्त वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान, कर्नाटक राज्य में पूरी तरह से / आंशिक रूप से पड़ने वाली 6100 करोड़ रु. की लागत वाली 421 किमी लंबाई की नई लाइन की 05 परियोजनाओं और 1073 करोड़ रु. की लागत वाली 131 किमी लंबाई की दोहरीकरण की 04 परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान, 253.4 किमी लंबाई की नई लाइन और 346.93 किमी लंबाई की दोहरीकरण परियोजनाओं को राज्य में चालू कर दिया गया है और इसी अवधि के दौरान राज्य के लिए कुल बजट परिव्यय 9699 करोड़ रु. था।

कर्नाटक राज्य में 3,772 करोड़ रु. की लागत वाली 3,379 मार्ग किमी की कुल 16 रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाएं योजना / निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। मार्च 2019 तक, 386 मार्ग किमी को विद्युत कर्षण पर चालू कर दिया गया है।

प्रत्येक परियोजना पर व्यय किए गए धन, धन के आबंटन और व्यय सहित सभी जारी कार्यों और नए कार्यों का विवरण, भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance(Budget) >2019-20_List_of_Works के तहत पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष बजट के साथ सदन में प्रस्तुत की गई पिंक बुक्स में भी उपलब्ध हैं।

(ग): कर्नाटक राज्य में पूरी तरह से / आंशिक रूप से पड़ने वाली 12 अदद नई लाइन परियोजनाओं के लिए 19892.69 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जिसमें से अब तक केवल 4507.83 एकड़ भूमि रेलवे को सौंपी गई है और 15384.86 एकड़ भूमि अभी भी शेष है, जिसे अभी कर्नाटक सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाना है और रेलवे को सौंपा जाना है।

(ङ) और (च): किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का अंतरण (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों पर), विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, प्रोत्साहन, भूकंप, बाढ, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल, माननीय न्यायालय के आदेश जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना की निष्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, जिसकी अंत में पूरा होने की स्थिति पर गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्र हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना बिना लागत में वृद्धि के पूरी हो जाएं, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाएं समय से भी पहले पूरी हों, रेलवे ने निविदा में बोनस उपनियम के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन की अवधारणा को अपनाया है जो परियोजना के निष्पादन की गति में और वृद्धि करेगा।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

****